covered under the negative list of Imports. Only some specified home electtronics items like colour TV sets of at»ove 30 inch size or audio systems of CIF value above US$500 can be imported against special import licences issued to Export Houses/ Trading House] Star Trading House/ Super Star Trading Houses.

(b) to (d) Do not arise.

**Settlement with All India Instramentation Ltd. Union**

5911. SHRI RAMACHANDRAN P1LX,AI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 3144 given in the Rajya Sabha on the 23rd December, 1993 and state:

(a) what are the reasons for entering into settlement by the Management of Instrumentation Ltd with a non-existent Bokaro unit of projects employees union even after prior information; and

(b) the steps taken against the officers responsible for such fraudulent deal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Instrumentation Lid. (IL) had entered into a tripartite agreement with All India Instrumeniation Ltd., Project Employee.s Union, Bokaro Branch in the Office of Joint Labour Commissioner Govt of Bihar on 20th June 1987, while the latter stating that the Bokaro unit of the Union has been dissolved, was received by IL subsequsntly on 7th August '87. The validity of the agreement was challenged by the Progressive Front in the Patna High Court of Munsif Magistrate, Chas. Both the cases have been dismissed.

(b) Does not arise.

**Establishment of Industrial Growth Centres in Arunachal Pradesh**

5912. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Go vernment had proposed to promote the process of industrial development by establishing industrial growth centres in the country;

(b) whether one such proposal was there for one of the backward States of North Eastern Region, i.e., Arunachal Pradesh; and

(c) if so, what are the reasons for delay in establishing industrial growth centre in Arunchal Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes^ Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Project report received from the State Government in Niklok Ngorlung growth centre is under appraisal with the lead agency.

**Fresh package of reforms**

5913. SHRI S. AUSTIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to offer a fresh package of reforms to appease foreign investors;

(b) if so, the details of the package; and

(c) the estimated foreign investments likely to come in the country after this new package?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) The foreign investment policy as enumerated in the Industrial Policy, 1991 is a continuing process and it is constantly kept under watch

by Government so as to take necessary measures to build on the gains already made, maintain a sustained growth in productivity and gainful employment and attain international competitiveness.

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहना**

**5914. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत आठ वर्षों में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस उपक्रम को अपने उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है ; और

(घ) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अपने स्तर पर क्या प्रयास किये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) कंपनी, 1988–89 के सिवाय, गत आठ वर्षों में लक्षित उत्पादन प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी है।

(ख) उत्पादन में यह कमी मूलत: धन की कमी के कारण थी जिससे समय पर उपयुक्त अंतर्वस्तुओं और आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति पर असर पड़ा। इसके अलावा, जरूरी उपकरण और मशीनरी की कम उपलब्धता, उच्च ऊपरी लागतों, अपर्याप्त और अनियमित विद्युत आपूर्ति और कभी-कभी क्रयादेशों की कमी से भी उत्पादन प्रभावित हुआ। घटिया कार्य-प्रणाली और उत्पादकता का भी इस पर प्रभाव पड़ा।

(ग) 1985–86 से 31 मार्च, 1994 तक, सरकार ने कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान की है जो 116.73 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में, 47.81 करोड़ रुपये योजना ऋण के रूप में, 166.85 करोड़ रुपये गैर-योजना ऋण के रूप में, 20.50 करोड़ रुपये गैर-योजना (स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम) के रूप में और 74.97 करोड़ रुपये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (अनुदान) के रूप में दी गई।

(घ) कंपनी द्वारा अपने कार्य निष्पादन में सुधार के लिए शुरू किए गए कुछ प्रमुख उपाय विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आरम्भ किये गये महत्वपूर्ण उपाय**

1. उत्पादन को इष्टतम करने के लिए फाऊण्ड्री फोर्ज संयंत्र से सहायक संयंत्रों में कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स की आपूर्ति को गहराई से मानीटर किया जा रहा है।

2. बेहतर कार्य प्रचालन के लिए फाऊण्ड्री फोर्ज संयंत्र (एफ. एफ. पी.) के अनुरक्षण संगठन को पुनर्गठित किया गया है।

3. पद्धतियों, कारपोरेट योजना तथा आई.इ.टी. जैसे निगम स्तर पर कुछेक मुख्य विभागों को सुदृढ़ एवं पुनर्गठित किया गया है।

4. अपशिष्टों को कम करने तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकीय क्षेत्र पर बल दिया गया है।

5. कंपनी के लिए आई.एस.ओ.–9000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।